

[2017] 4 एस.सी.आर. 625

पुनः तमिलनाडु राज्य में अनाथालयों में बच्चों का शोषण

बनाम भारत संघ और अन्य

(रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 102, 2007)

मई 05, 2017

(मदन बी. लोकर और दीपक गुप्ता, जे.जे.)

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:

धारा 2(14) - देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे - देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे कौन हैं - यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) के प्रावधानों में देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे की कोई परिभाषा नहीं दी गई है - यौन शोषण या यौन हमले या यौन उत्पीड़न का शिकार बच्चा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा है - इसी तरह, किसी अपराध का आरोपी और किशोर न्याय बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष लाया गया बच्चा भी देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा हो सकता है - हालाँकि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2(14) में परिभाषित किया गया है, लेकिन परिभाषा में बच्चों की कुछ श्रेणियों को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है - परिणामस्वरूप, चूँकि किशोर न्याय अधिनियम बच्चों के लाभ के लिए है और उनके अधिकारों की रक्षा और पालन-पोषण करने के लिए है, इसलिए देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे की परिभाषा को व्यापक व्याख्या दी जानी चाहिए - इसमें निम्नलिखित भी शामिल होना चाहिए यौन शोषण या यौन हमले या यौन उत्पीड़न के शिकार, पोक्सो अधिनियम के तहत और साथ ही बाल तस्करी के शिकार - ऐसे बच्चों को जेजे अधिनियम के प्रावधानों के तहत संरक्षण दिया जाना चाहिए जो पोक्सो अधिनियम और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत अपराध के शिकार हैं - बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005

- बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 - यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 - अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 - बाल दुर्व्यवहार - बच्चों की तस्करी।

धारा 41 - बाल देखभाल संस्थान - आश्रय गृह - देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को ऐसे घरों में आश्रय दिया जाता है जो राज्य सरकार या गैर सरकारी संगठनों या स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रबंधित होते हैं - जेजे अधिनियम की धारा 41 जो अनिवार्य करती है, इसके बावजूद किसी अन्य कानून/तत्समय लागू किसी कानून में निहित किसी भी बात के अनुसार, सभी संस्थाएं, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा संचालित हों या स्वैच्छिक संगठनों या गैर सरकारी संगठनों द्वारा, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के आवास के लिए हैं, उन्हें किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार पंजीकृत किया जाएगा, जैसा कि उक्त अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर निर्धारित किया जा सकता है। बाल न्याय अधिनियम 15 जनवरी, 2016 को लागू हुआ, लेकिन पंजीकरण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। केंद्र सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे 31 दिसंबर, 2017 तक सभी बाल देखभाल संस्थानों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लें, जिसमें संपूर्ण डेटा की पुष्टि और सत्यापन किया जाना चाहिए। पंजीकरण प्रक्रिया में देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले सभी बच्चों का डेटाबेस भी शामिल होना चाहिए, जिसे हर महीने अपडेट किया जाना चाहिए। डेटाबेस बनाए रखते समय, संबंधित अधिकारियों द्वारा गोपनीयता और निजता के मुद्दों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) बच्चों के) मॉडल नियम, 2016 - r.21.

बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के न्यूनतम मानक - सीआरसी का अनुच्छेद 3(3) विशेष रूप से राज्य पक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थाएं सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करेंगी, विशेष रूप से सुरक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारियों और पर्यवेक्षण के क्षेत्रों में। हालांकि, संस्थाओं के लिए निर्धारित देखभाल

के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है यदि बाल देखभाल संस्था की पहचान नहीं की गई है और उसका पंजीकरण नहीं किया गया है। आदर्श नियम बाल देखभाल संस्थाओं के स्टाफिंग पैटर्न, भौतिक अवसंरचना, कपड़े, बिस्तर, प्रसाधन सामग्री और अन्य वस्तुएं, स्वच्छता और सफाई, दैनिक दिनचर्या, पोषण और आहार पैमाने, चिकित्सा स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक और मनोरंजक सुविधाओं और ऐसे बच्चों के पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण के लिए वास्तविक प्रयासों से संबंधित हैं। बाल देखभाल संस्थाओं के पंजीकरण के अभाव में ये सभी आवश्यकताएं अप्रवर्तनीय हो जाती हैं। यदि राज्य के अधिकारी यह सुनिश्चित नहीं करते हैं कि बाल देखभाल संस्थाओं में देखभाल के न्यूनतम मानकों का पालन किया जाता है, तो वे लापरवाही के दोषी हो सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे जेजे अधिनियम और मॉडल नियमों के अनुसार देखभाल के न्यूनतम मानकों को 31 दिसंबर, 2017 तक या उससे पहले लागू करें - किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) मोड/नियम, 2016 - बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (सी.आर.सी.) - अनुच्छेद 3(3)।

जेकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य [2005] 2 अनुपूरक एससीआर 307: (2005) 6 एससीसी 1

- पर भरोसा किया गया।

चार्ल्सवर्थ और पर्सी लापरवाही पर एल.ओ.एच. संस्करण (2001) - संदर्भित।

अनुदानों का उपयोग - यह राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। - समस्या यह है कि उपलब्ध अनुदानों का लाभकारी उपयोग करने की इच्छाशक्ति का अभाव है। - राज्य अपने दायित्वों से बचने के लिए अनुदानों की अनुपलब्धता को अनुदानों के अकुशल उपयोग के साथ नहीं जोड़ सकते। - राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए गए

अनुदानों (व्यय विवरण के साथ) के पूर्ण और उचित उपयोग के लिए योजनाएँ बनाने का निर्देश दिया जाता है।

राष्ट्रीय और राज्य आयोग - स्थापना - सीपीसीआर अधिनियम में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) के गठन का प्रावधान है - इन आयोगों का उद्देश्य सीपीसीआर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करना है - पोक्सो अधिनियम के कार्यान्वयन में एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं - पोक्सो अधिनियम की धारा 44 एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर के कंधों पर बहुत अधिक बोझ डालती है - यह जरूरी है कि एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर को सीपीसीआर अधिनियम और पोक्सो अधिनियम के अनुसार और केवल बच्चों के लाभ के लिए कार्य करने की अनुमति दी जाए - इन आयोगों का दायित्व है कि वे जहां भी आवश्यक हो, संवैधानिक न्यायालयों से संपर्क करने सहित कार्रवाई करें - इन आयोगों का दायित्व है कि वे वार्षिक रिपोर्ट और यदि आवश्यक हो तो विशेष रिपोर्ट तैयार करें, लेकिन यह बताया गया है कि इस आवश्यकता को शायद ही लागू किया गया है, मुख्य रूप से इन आयोगों की रुचि की कमी के कारण कानून के तहत काम करने में कमी आई है और आंशिक रूप से इन आयोगों में बड़ी संख्या में रिक्तियां होने के कारण भी - जहां भी बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग की स्थापना नहीं की गई है या स्थापित होने के बावजूद भी वह अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। अध्यक्ष या किसी एक या अधिक सदस्यों की अनुपस्थिति में पूर्णतः कार्यात्मक होने के लिए, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी रिक्तियां 31 दिसंबर, 2017 तक या उससे पहले समर्पित व्यक्तियों द्वारा भरी जाएं - इस प्रकार गठित एससीपीसीआर को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी ताकि सभी को उनकी गतिविधियों के बारे में पता हो और वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लाभ के लिए योगदान दे सकें - बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम,

धारा 53, 54 - पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण - देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति के संबंध में, जेजे अधिनियम में धारा 53 जैसे अनिवार्य प्रावधान हैं जो बाल देखभाल संस्थानों में पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण सेवाओं से संबंधित हैं - इस प्रावधान के तहत राज्य को ऐसे संस्थानों में बच्चों की बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जहां आवश्यक हो कानूनी सहायता और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सहायता शामिल है। पहचान का प्रमाण प्राप्त करना - पहचान का प्रमाण बच्चे के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, अन्यथा वह मात्र एक आंकड़ा बनकर रह जाता है - पुनर्वास और पुनः एकीकरण सेवाओं के प्रावधान के कई पहलू हैं और इसे अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है, बल्कि इसे अन्य बातों के साथ-साथ जेजे अधिनियम की धारा 54 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें उक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों का निरीक्षण करने की आवश्यकता है - निरीक्षण समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है, जो कम से कम तीन सदस्यों की एक टीम में, जिनमें से कम से कम एक महिला और एक चिकित्सा अधिकारी होगा, आवंटित क्षेत्र में बच्चों को रखने वाली सभी सुविधाओं का अनिवार्य रूप से दौरा करेगी। - यह अनिवार्य है कि केंद्र सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए - कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि सहित भारत सरकार की कई योजनाएं हैं, जिनका लाभ उठाया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों का पुनर्वास करें।

व्यक्तिगत बाल देखभाल योजनाएँ - व्यक्तिगत बाल देखभाल योजनाओं की तैयारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बाल देखभाल संस्थान में प्रत्येक बच्चे के लिए एक बाल देखभाल योजना हो - हालाँकि यह प्रक्रिया लंबी और बोझिल लग सकती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में इसकी आवश्यकता को कम करके नहीं आंका जा सकता है -

व्यक्तिगत बाल देखभाल योजनाएँ तैयार करने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है और इसे तुरंत शुरू किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक बाल देखभाल संस्थान में प्रत्येक बच्चे के लिए 31 दिसंबर 2017 तक या उससे पहले एक व्यक्तिगत बाल देखभाल योजना तैयार की जानी चाहिए।

कार्मिकों का प्रशिक्षण - मॉडल नियमों का नियम 89 बच्चों से निपटने वाले कार्मिकों के प्रशिक्षण से संबंधित है - यह नियम बी जेजे अधिनियम के तहत विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों को न्यूनतम 15 दिनों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, जिसमें बाल न्यायालयों के कर्मचारी, प्रधान मजिस्ट्रेट और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष और सदस्य, बाल देखभाल संस्थानों के प्रभारी व्यक्ति सहित पुलिस अधिकारी आदि शामिल हैं। मॉडल नियमों का नियम 89 यह भी मानता है कि राज्यों में न्यायिक अकादमी और पुलिस अकादमी के साथ-साथ राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण उचित प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करते हैं और कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं - अप्रशिक्षित या अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कार्मिक अनजाने में बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। यौन शोषण या यौन हमले या यौन उत्पीड़न के शिकार - पर्याप्त संख्या में अकादमियां हैं जो इस कार्य को कर सकती हैं, जिनमें राज्यों में पुलिस अकादमियां और न्यायिक अकादमियां शामिल हैं - राष्ट्रीय स्तर के निकाय भी हैं जो प्रशिक्षण की इस प्रक्रिया में सहायता कर सकते हैं, जिनमें पुलिस अनुसंधान और प्रशिक्षण ब्यूरो, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और स्थापित गैर सरकारी संगठन जैसे निकाय शामिल हैं - जहां भी संभव हो, प्रशिक्षण मॉड्यूल जल्द से जल्द तैयार किए जाने चाहिए - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 - नियम 89.

44, 45 - गैर-संस्थागतीकरण - सीआरसी का अनुच्छेद 20 राज्य पक्षों को अस्थायी या स्थायी रूप से पारिवारिक वातावरण से वंचित बच्चों को विशेष सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य करता है - अनुच्छेद 20 पालक नियुक्ति, गोद लेने या यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त संस्थान में नियुक्ति के रूप में वैकल्पिक देखभाल को दर्शाता है - यह स्पष्ट है कि अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला विकल्प देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे का संस्थागतकरण नहीं होना चाहिए और यह अंतिम उपाय है - सीआरसी का अनुच्छेद 40 (4) कानून का उल्लंघन करने के आरोपी बच्चों से संबंधित है, यह भी कहता है कि राज्य पक्ष "देखभाल, मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण, परामर्श, परिवीक्षा, पालक देखभाल, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण और संस्थागत देखभाल के अन्य विकल्प" सुनिश्चित करेंगे - वास्तव में, सीआरसी की भावना को ध्यान में रखते हुए, जेजे अधिनियम स्वयं संस्थागतकरण के लिए गोद लेने जैसे विकल्पों को प्रोत्साहित करता है (अध्याय VIII)। पालक देखभाल (धारा 44) और प्रायोजन (धारा 45) - संघ सरकार ने तब से गोद लेने के नियम, 2017 के साथ-साथ पालक देखभाल के लिए मॉडल दिशानिर्देश, 2016 तैयार किए हैं - इन्हें सभी संबंधितों द्वारा लागू किया जाना चाहिए, जिसमें न्यायालय भी शामिल हैं, विशेष रूप से गोद लेने के मुद्दों से निपटने वाले - हालांकि, जेजे अधिनियम, मॉडल नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की समझ और प्रशंसा में प्रशिक्षण अनिवार्य है और इन दस्तावेजों की प्रतियां संबंधित कर्मियों को सौंपना ही पर्याप्त नहीं है, भले ही वे न्यायिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी या सरकारी कर्मचारी हों - यह आवश्यक नहीं है कि देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले हर बच्चे को बाल देखभाल संस्थानों में रखा जाए - गोद लेने और पालक देखभाल जैसे विकल्पों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है - बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (सीआरसी) - कला 20, 40।

किशोर न्याय समिति - उच्च न्यायालयों ने यह सुनिश्चित करना संवैधानिक दायित्व है कि बच्चों सहित सभी नागरिकों के अधिकारों को संविधान के तहत संरक्षित, संरक्षित और सम्मानित किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए, सभी उच्च न्यायालयों ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों

से मिलकर किशोर न्याय समिति का गठन किया है और ये समितियां यह सुनिश्चित करती हैं कि 4ct के प्रावधानों को अक्षरशः लागू किया जाए। पुलिस सहित राज्य के संबंधित अधिकारियों का भी यह दायित्व है कि वे किशोर न्याय अधिनियम और संवैधानिक दृष्टि द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक किशोर न्याय समिति को सभी सहायता प्रदान करें। कम से कम समय में सफलतापूर्वक प्राप्त किए जाएं - राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे किशोर न्याय अधिनियम और आदर्श नियमों के अनुसार निरीक्षण समितियों का गठन करें ताकि बाल देखभाल संस्थानों का नियमित निरीक्षण किया जा सके और ऐसे निरीक्षणों की रिपोर्ट तैयार की जा सके ताकि इन संस्थानों में बच्चों की जीवन स्थितियों में सकारात्मक बदलाव आए - इन निरीक्षण समितियों का गठन 31 जुलाई, 2017 को या उससे पहले किया जाना चाहिए और उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में बाल देखभाल संस्थानों का पहला निरीक्षण करना चाहिए और 31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए - जबकि प्रत्येक उच्च न्यायालय में किशोर न्याय समिति किशोर न्याय अधिनियम और आदर्श नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभा रही है, प्रत्येक समिति को एक छोटे सचिवालय की आवश्यकता होगी। सहायता का तरीका - किशोर न्याय समिति अपनी सहायता के लिए सचिवालय स्थापित करने पर गंभीरता से विचार करेगी - प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्येक उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति को सहायता प्रदान करें और इस संबंध में किशोर न्याय समिति के साथ सहयोग करें।

सामाजिक अंकेक्षण - आवश्यकता - यह सुनिश्चित करने के लिए कि किशोर न्याय अधिनियम का कार्यान्वयन सही दिशा में हो रहा है, यह आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ष सामाजिक अंकेक्षण किया जाए - सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता न केवल आत्मनिरीक्षण के लिए बल्कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए भी आवश्यक है - सामाजिक अंकेक्षण करने से बचने का कोई कारण नहीं हो सकता है, खासकर तब जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय

ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के साथ-साथ एकीकृत बाल संरक्षण योजना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया गया है - यह आवश्यक है कि सामाजिक अंकेक्षण करने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ-साथ प्रत्येक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर - बाल देखभाल संस्थानों के अभिलेखों का रखरखाव - देश में सभी बाल देखभाल संस्थानों का कोई डेटाबेस नहीं है - राज्य सरकारों ने उपलब्ध आंकड़ों को सत्यापित नहीं किया है या केंद्र सरकार के सहयोग से बाल देखभाल संस्थानों की मैपिंग नहीं की है - यह एक आवश्यक पहला कदम है क्योंकि यह कल्पना करना मुश्किल है कि बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों की देखभाल कैसे की जा सकती है। यदि संस्थानों की संख्या, ऐसे संस्थानों में बच्चों की संख्या, बच्चों के बारे में प्रासंगिक जानकारी आदि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। - इसलिए, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और बाल देखभाल संस्थानों के अभिलेखों के संग्रह, संशोधन और पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी का अच्छा उपयोग किया जा सकता है - यह केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए भी अनिवार्य है कि वे सभी बाल देखभाल संस्थानों की पूरी सूची उनके पते और प्रभारी व्यक्ति या प्रमुख अधिकारी के साथ-साथ इन बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों का पूरा विवरण तैयार करें। - यह सभी जानकारी की उपलब्धता केवल सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से ही संभव है।

प्रौद्योगिकी

और एक विशाल कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम - सिमिलाडी, प्रभावी के लिए किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें कंप्यूटर और प्रिंटर के साथ-साथ निर्बाध बिजली आपूर्ति इकाइयों से सुसज्जित किया जाए ताकि उनके दैनिक कामकाज का ध्यान रखा जा सके।

कानूनों की व्याख्या - लाभकारी कानून :: जैसे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - व्याख्या - माना गया: लाभकारी कानून न्यायालयों और सभी संबंधितों द्वारा व्यापक दृष्टिकोण की मांग करते हैं - अन्याय को रोकने या न्याय को बढ़ावा देने और कल्याण कानून के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए, व्यापक व्याख्या दी जानी चाहिए, भले ही इसके लिए शाब्दिक निर्माण से हटना पड़े - देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे की परिभाषा जेजे अधिनियम की धारा 2 (14) में दी गई है, इसकी व्यापक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए - इसे संपूर्ण नहीं बल्कि उदाहरणात्मक और आवश्यकताओं को आगे बढ़ाने वाला माना जाना चाहिए। सामाजिक न्याय का - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - धारा 2(14)।

वर्कमैन बनाम अमेरिकन एक्सप्रेस प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग निगम (1985) 4 एससीसी 71; क्षेत्रीय निदेशक, ईएस कॉर्पोरेशन बनाम फ्रांसिस डी कोस्टा [1992] 3 एससीआर 23: 1993 सप (4) धारा 100; एमएसआर लेदर्स बनाम एस. पलानीअप्पन [2012] 9 एससीआर 165: (2013) 1 एससीसी 177; बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे [2013] 10 एससीआर 259: (2014) 1 एससीसी 188; अभिराम सिंह बनाम सी.डी. कॉमाचेन [2017] 1 एससीआर 158: (2017) 2 एससीसी 629 - पर भरोसा किया।

भारत का संविधान - अनुच्छेद 39(जे) - यद्यपि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक हैं, वे लागू करने योग्य नहीं हैं - हालांकि, एक बार जब कोई निर्देशक सिद्धांत कानून के माध्यम से लागू हो जाता है, तो राज्य को अपने संवैधानिक दायित्व को बनाए रखने के लिए कानून को लागू करने के लिए बाध्य होना चाहिए - जेजे अधिनियम राज्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 39(ज) के तहत विशेष रूप से बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थिति में विकसित होने के अवसर देकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का सम्मान करने का एक माध्यम है - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015.

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ [1984] 2

एससीआर 67: (1984) 3 एससीसी 161 - पर निर्भर।

बाल अधिकारों पर कन्वेंशन: अनुच्छेद 19- भारत ने 11 दिसंबर, 1992 को बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (सीआरसी) को स्वीकार किया - सीआरसी का अनुच्छेद 19 राज्य दलों को बाध्य करता है कि वे बच्चे को सभी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा, चोट या दुर्व्यवहार, उपेक्षा या लापरवाहीपूर्ण व्यवहार, दुर्व्यवहार या शोषण, जिसमें यौन शोषण - बच्चों की तस्करी - बाल शोषण शामिल है, से बचाने के लिए सभी उचित विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय करें।

कानून पर भरोसा किया गया

[1984] 2 एससीआर 67	पर निर्भर करता है	पैरा 13
(1985) 4 अनुच्छेद 71	पर निर्भर करता है	पैरा 19
[1992) 3 एससीआर 23	पर निर्भर करता है	पैरा 20
[2012) 9 एससीआर 165	पर निर्भर करता है	पैरा 21
[2013) 10 एससीआर 259	पर निर्भर	पैरा 21
[2017) 1 एससीआर 158	पर निर्भर	पैरा 21
[2005) 2 अनुपूरक एससीआर 307	पर निर्भर	पैरा 31

आपराधिक मूल अधिकार क्षेत्र: रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 102 दिनांक 2007.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

मनिंदर सिंह, एएसजी, सुश्री वी. मोहना, बसंत आर, सीनियर एडवोकेट, पुरुषेंद्र कौरव, एएजी, सुश्री अपर्णा भट (एसी), सुश्री जोशीता पाई, मयंक सपरा, के. परमेश्वर, मीनेश क्र. दुबे, सुश्री रशर्नि मल्होत्रा, बी.के. प्रसाद, एस.ए. हसीब, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, जी.एस. मक्कड़, रवीन्द्र कुमार वर्मा, मुकुल सिंह, मुकेश कुमार मरोरिया, सुश्री मुनमुन गोस्वामी, रोहित राव एन, मुकुंद पी. एलजेनी,

श्रीमती अनिल कटियार, सुश्री सुषमा सूरी, सुश्री अनिदिता पुजारी, अशोक के. श्रीवास्तव, सुश्री बांसुरी स्वराज, प्रतीक रूसिया, सुश्री श्रेया भटनागर, सी. डी. सिङ्घ, राघेथ बसंत, सुश्री आंचल टिकमानी, मिशा! जौहरी, सलाह. उपस्थित पक्षों के लिए.

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

मदन बी. लोकर, न्यायमूर्ति

1. इस रिट याचिका 4 जुलाई, 2007 को हिंदी समाचार पत्र "हिंदुस्तान" (लखनऊ संस्करण) में प्रकाशित एक लेख का आधार पर विचार किया गया था। लेख सुश्री अंजलि सिन्हा द्वारा लिखा गया था और लेख का अनुवादित शीर्षक "अनाथालय या बाल शोषण के लिए स्थान " है।लेख को ए. एस. चौधरी द्वारा एक पत्र के साथ इस न्यायालय को भेजा गया था और यह इस याचिका की उत्पत्ति है जिसे 10 सितंबर, 2007 को एक जनहित याचिका (पी. आई. एल.) के रूप में दर्ज किया गया था। सुश्री अपर्णा भट को इस न्यायालय की सहायता के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया था। शुरुआत में हमें सुश्री अपर्णा भट द्वारा पिछले 10 वर्षों में इस मामले में सहायता प्रदान करने के लिए किए गए अथक और उत्कृष्ट प्रयासों को स्वीकार करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए।

2. व्यापक तौर पर, सुश्री अंजलि सिन्हा द्वारा लिखे गए लेख में उल्लेख किया गया है कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम में गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ सरकारी संस्थानों द्वारा संचालित अनाथालय कथित तौर पर बच्चों के व्यवस्थित यौन शोषण में शामिल थे। एक स्टिंग ऑपरेशन ने संकेत दिया कि बच्चों की यौन सेवाएँ विदेशियों के साथ-साथ भारतीय पर्यटकों को भी प्रदान की जा रही थीं और जिन बच्चों की यौन सेवाएँ ली जा रही थीं, उनकी दरें टेलीफोन पर या अनाथालय में एक बैठक में तय की गई थीं।

3. यह आगे कहा गया है कि तमिलनाडु में राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और यह स्वीकार किया गया कि सरकारी स्कूल यौन शोषण के कारण लड़कियों के लिए असुरक्षित हो गए हैं। एक आठ वर्षीय लड़की की घटना का उल्लेख किया गया था जिसे उसके प्रिंसिपल द्वारा परेशान किया गया था और यह उल्लेख किया गया था कि प्रिंसिपल को केवल सजा के रूप में स्थानांतरित किया गया था। एक अन्य घटना का उल्लेख

किया गया जहां स्कूल के शिक्षक ने छात्रों के साथ अन्य छात्रों के मौजूदगी में बंद कमरे में दुर्व्यवहार किया।

4. साथ में तत्कालीन परिवार और बाल कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ बच्चों की स्थिति पर एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि 53 प्रतिशत बच्चे यौन शोषण से पीड़ित हैं। बच्चों को संस्थागत दुर्व्यवहार के साथ साथ उनके रिश्तेदार द्वारा भी दुर्व्यवहार का विषय होना पड़ता है।

5. इन व्यापक तथ्यों पर सुश्री अंजलि सिन्हा ने सुझाव दिया कि विशेष रूप से सरकारी संस्थानों में बच्चों के यौन शोषण की समस्या एक गंभीर समस्या बन गई है और इसके तत्काल निवारण की आवश्यकता है। उन्होंने प्रत्येक स्कूल में एक परामर्श प्रकोष्ठ सहित कुछ सुझाव दिए जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि दुर्व्यवहार को कैसे पहचाना जाए और ऐसी किसी भी घटना के मामले में बच्चों के लिए सुलभ एक शिकायत तंत्र प्रदान किया जाए।

इस न्यायालय में कार्यवाही

6. इन वर्षों में, इस न्यायालय ने कई आदेश पारित किए और उन्होंने उल्लेख किया कि बच्चों की तस्करी, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा कब्जा किए जा रहे स्कूलों और बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी जैसे कुछ अन्य मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय ने सामान्य रूप से बच्चों के अधिकारों को शामिल करने के लिए इस जनहित याचिका के दायरे का विस्तार करने की मांग की।

7. 7 फरवरी, 2013 को पारित एक आदेश में विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा विभिन्न आदेश जारी करने का मुख्य कारण यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों के अधिकारों के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य में बच्चों को उचित सुविधाओं के प्रावधानों को लागू किया जाए। यह प्रस्तुत किया गया था कि स्पष्ट रूप से बच्चों के अधिकारों को पर्याप्त रूप से तभी सुरक्षित किया जा सकता है जब बाल अधिकार संरक्षण आयोग

अधिनियम, 2005, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 जैसे बच्चों से संबंधित कानूनों में निहित निगरानी और नियंत्रण प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया जाए।

8. इस न्यायालय द्वारा 16 दिसंबर, 2013 को एक विस्तृत आदेश पारित किया गया था जिसमें शोक व्यक्त किया गया था कि जारी किए गए निर्देशों के बावजूद, राज्यों द्वारा बच्चों के अधिकारों की रक्षा में बहुत कम या कोई प्रगति नहीं हुई थी। जहाँ तक बाल अधिकार संरक्षण आयोगों का संबंध है, वे यह केवल कागज पर मौजूद हैं क्योंकि कुछ मामलों में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई थी या सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई थी या कोई नियम और एफ विनियम नहीं बनाए गए थे। इस न्यायालय ने कहा कि जिस अभावपूर्ण तरीके से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बच्चों के अधिकारों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उससे बच्चों को गारंटीकृत संवैधानिक अधिकारों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक हो गया है। यह देखा गया कि राज्यों की निष्क्रियता इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रतिकूल थी और इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह समझना चाहिए कि उन्हें भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम करना है।

9. तदनुसार, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में विशिष्ट जानकारी मांगी गई थी। बच्चों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित कानूनों के कार्यान्वयन में संबंधित सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में इस न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समय-समय पर हलफनामे दायर किए गए थे। उस समय प्रतिक्रियाएं निराशाजनक थीं और इस अदालत के मामले में संज्ञान लेने के लगभग एक दशक बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रगति, यदि कोई हुई भी, तो मामूली रही है। दुर्भाग्य से, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को बच्चों के लिए सुधारात्मक उपाय या सक्रिय चिंता बहुत कम है।

10. 20 मार्च, 2015 को इस न्यायालय ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 64 और एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए धन के उपयोग के संदर्भ में सामाजिक ऑडिट की आवश्यकता को उठाया।
11. 17 अप्रैल, 2015 को इस न्यायालय ने एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत समवर्ती निगरानी अंकेक्षण के साथ-साथ किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियाँ, विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ, बाल देखभाल संस्थानों का कार्य और दत्तक ग्रहण करने वाली एजेंसियों का कार्य का मुद्दा उठाया
12. 31 जुलाई, 2015 को विद्वान न्यायमित्र के कहने पर, सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए एक नीति निर्धारित करने के अलावा बाल देखभाल योजना तैयार करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। 28 अगस्त, 2015 को इस न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में रिक्तियों का मुद्दा उठाया गया था। 30 अक्टूबर, 2015 को सामाजिक अंकेक्षण के प्रारूप पर चर्चा की गई और ताकि कुछ कार्यक्षम और व्यावहारिक मुद्दे को अंतिम रूप दिया जा सके।
13. चूंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि गंभीरता की कमी थी और अधिक दुखद रूप से कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बच्चों की भलाई और कल्याण के प्रति सहानुभूति की कमी और बाल यौन शोषण की परेशान करने वाली बढ़ती घटनाओं के संबंध में पूर्ण उदासीनता, अक्सर किसी अधिकारी के पद पर रहने वाले व्यक्ति द्वारा और संसद द्वारा पारित कानूनों के अप्रभावी कार्यान्वयन के कारण संसदीय विधान अप्रासंगिक हो जाते हैं। , हमने उचित निर्देश पारित करने के इरादे से सभी दलों की विस्तृत दलीलें सुनीं ताकि संसद द्वारा पहले से अधिनियमित कानूनों का सार्थक कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। यह सराहना की जानी चाहिए कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकास करने के अवसर देकर विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 39 (च) ए के तहत राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत राज्य

के लिए बच्चों को सम्मान देने का एक माध्यम है। वास्तव में, हालांकि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक हैं, लेकिन वे लागू करने योग्य नहीं हैं, जैसा कि **बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ** में माना गया है, कि एक बार एक निर्देशक सिद्धांत को कानून के माध्यम से लागू करने के बाद राज्य को अपने संवैधानिक दायित्व को बनाए रखने के लिए कानून को लागू करने के लिए बाध्य होना चाहिए।

14. इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना उचित है कि भारत ने 11 दिसंबर, 1992 को बाल अधिकारों पर समझौते (सी. आर. सी.) को स्वीकार कर लिया था। सी. आर. सी. का अनुच्छेद 19 राज्य दलों को " बच्चे को यौन शोषण सहित सभी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा, चोट या दुर्व्यवहार, उपेक्षा या लापरवाही व्यवहार, दुर्व्यवहार या शोषण से बचाने के लिए सभी उचित विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय लेने के लिए बाध्य करता है।

15. इन सब को ध्यान में रखते हुए, विद्वान न्यायमित्र ने तीन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, अर्थात् (1) देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे; (2) तस्करी के शिकार बच्चे (3) सड़क पर रहने वाले बच्चे। हम तस्करी या सड़क पर रहने वाले बच्चों की दुर्दशा पर विचार करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, क्योंकि इसका मतलब सुश्री अंजलि सिन्हा द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हम तस्करी किए गए बच्चों और सड़क पर रहने वाले बच्चों के मुद्दों को उपयुक्त मामला में विचार के लिए खुला छोड़ते हैं।

16. देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के अधिकारों पर यह प्रस्तुत किया गया कि बाल देखभाल संस्थानों से संबंधित मुद्दों, चाहे वे राज्य सरकार या गैर सरकारी संगठनों या अन्य स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रबंधित हों, को देखभाल के कुछ न्यूनतम मानकों का पालन करने की आवश्यकता है और इसके अलावा, ऐसे बच्चों का पुनर्वास प्राथमिकता होनी चाहिए।

देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे

17. देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे कौन हैं? यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में 'पॉक्सो अधिनियम') के प्रावधान देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे की कोई परिभाषा प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि यौन दुर्व्यवहार या यौन हमले या यौन उत्पीड़न का शिकार बच्चा देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाला बच्चा है। इसी तरह किसी मामले में, एक बच्चे पर अपराध का आरोप लगाया जाता है और उसे किशोर न्याय बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष लाया जाता है देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाला बच्चा भी हो सकता है।

18. भले ही देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (इसके बाद जेजे अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 2 (14) में परिभाषित किया गया है, परिभाषा में बच्चों की कुछ श्रेणियों को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है। नतीजतन, हमारा विचार है कि चूंकि जेजे अधिनियम बच्चों के लाभ के लिए है और इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है, इसलिए बच्चे की परिभाषा देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि बच्चों की कुछ श्रेणियों को परिभाषा से बाहर रखा जाता है, भले ही उन्हें उतनी ही देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है जितनी कि परिभाषा में विशेष रूप से सूचीबद्ध बच्चों की श्रेणियों को, जिस तरह के लाभकारी कानूनों से हम निपट रहे हैं, वे अदालतों और सभी संबंधितों द्वारा एक विस्तृत सी दृष्टिकोण की मांग करते हैं।

19. **वर्कमेन बनाम अमेरिकन एक्सप्रेस अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग निगम का प्रबन्ध²** में इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 में कहा कि:

" वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं। सामाजिक कल्याण कानून और मानवाधिकार कानून जैसे उदार महत्व के कानूनों में आने वाले शब्दों को प्रोक्रस्टियन बेड (एकरूपता या अनुरूपता) में नहीं रखा जाना चाहिए या लिलिपुटियन

आयामों में संकुचित नहीं किया जाना चाहिए। इन कानूनों को लागू करने में शाब्दिक व्याख्या का ढोंग नहीं होना चाहिए इससे बचा जाना चाहिए और इसके दुरुपयोग को पहचाना जाना चाहिए और कम किया जाना चाहिए।

20. **क्षेत्रीय निदेशक, ई. एस. आई.निगम बनाम फ्रांसिस डी costa³**में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था। जब यह देखा गया कि "यह स्थापित कानून है कि अन्याय को रोकने या न्याय को बढ़ावा देने और कल्याणकारी कानून के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए, व्यापक व्याख्या दी जानी चाहिए, भले ही इसके लिए शाब्दिक व्याख्या से विचलन की आवश्यकता हो।"

21.⁴ किसी कानून के एक प्रावधान की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करने आवश्यकता **एमएसआर लेदर्स बनाम एस पलानीअप्पन** में मान्यता दी गई 'जब इस न्यायालय ने कहा कि:

" विधियों की व्याख्या के हितकारी सिद्धांतों में से एक ऐसी व्याख्या को अपनाना है जो उस उद्देश्य को बढ़ावा देती है और आगे बढ़ाती है जिसे कानून द्वारा प्राप्त करने की मांग की थी, ना कि एक ऐसी व्याख्या को प्राथमिकता देते हुए जो इस तरह के उद्देश्य को पराजित करती है। इस न्यायालय ने निर्णयों की एक लंबी शृंखला में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को न्यायालय द्वारा वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय अपनाए जाने के लिए सिद्धांत के रूप में मान्यता दी है।

इसी प्रकार का दृष्टिकोण, हालांकि एक अलग संदर्भ में, **बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे⁵** में व्यक्त किया गया था। इस पर अधिक विस्तृत चर्चा इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले **अभिराम सिंह बनाम सी. डी. कॉमाचेन⁶** में पाया जाता जाना है।

22. इस संदर्भ में यदि , जेजे अधिनियम की धारा 2 (14) में दी गई देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे की परिभाषा को पढ़ें तो इसे एक व्यापक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दी जानी चाहिए-इसे संपूर्ण नहीं बल्कि उदाहरणात्मक और सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं को आगे बढ़ाने

के रूप में माना जाना चाहिए। यह समझ सी. आर. सी. सी. के अनुच्छेद 40 के अनुरूप भी होगी जिसमें कहा गया है कि "राज्य पक्ष किसी अपराध के आरोपी प्रत्येक बच्चे के अधिकारों को मान्यता देंगे और ऐसे बच्चे के साथ व्यवहार बच्चे की गरिमा और मूल्य को बढ़ावा देने के अनुरूप होगा"।

23. विद्वान न्यायमित्र ने कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे के डी अर्थ के लिए एक व्यापक आधारित दृष्टिकोण अपनाया है और कुछ अन्य उच्च न्यायालयों ने तुलनात्मक रूप से संकीर्ण व्याख्या को अपनाया है। ये निर्णय किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के संदर्भ में दिए गए थे और जहां तक जेजे अधिनियम का संबंध है, वे वास्तव में लागू नहीं होंगे। हालाँकि, यह उनके इस कथन से विचलित नहीं करता है कि देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए और जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कानून के साथ संघर्ष में कुछ बच्चों के अलावा, इसमें पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन शोषण या यौन हमले या यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के साथ-साथ बाल तस्करी के पीड़ित भी शामिल होने चाहिए। पॉक्सो अधिनियम और अनैतिक एफ दुर्व्यापार यातायात (निवारण रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत अपराध का शिकार होने वाले ऐसे बच्चों को जेजे अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी सुरक्षा दी जानी चाहिए।

बाल देखभाल संस्थान

24. देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को उन घरों में आश्रय दिया जाता है जो राज्य सरकार या गैर सरकारी संगठनों या स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। इस संदर्भ में, जेजे अधिनियम की धारा 41 की ओर जी का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, जो किसी भी चीज के बावजूद अनिवार्य है। उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित है कि सभी संस्थान, 3 (2014) 1 एस. सी. सी. 188 6 (2017) 2 एस. सी. सी. 629 एच [2017] 4 एस. सी. आर. 640 चाहे वह राज्य सरकार द्वारा या स्वैच्छिक संगठनों या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित हो, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के आवास के लिए हैं, उन्हें जेजे

अधिनियम के तहत उस तरीके से पंजीकृत किया जाएगा जो उक्त अधिनियम के शुरू होने के छह महीने के भीतर निर्धारित किया जाए। जेजे अधिनियम 15 जनवरी, 2016 को लागू हुआ था, लेकिन हमें सूचित किया गया कि पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है और अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। ।

25. इस दिन और युग में जब उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और देश में श्रमशक्ति की कोई कमी नहीं है, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि जेजे अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों को अभी तक पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया गया है, विशेष रूप से बाल देखभाल संस्थाओं के पंजीकरण के संबंध में। यह पता लगाना लगभग असंभव है कि चार दीवारों के भीतर क्या हो रहा है। सुश्री अंजलि सिन्हा का लेख इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि बाल देखभाल संस्थानों में क्या हो सकता है। लेख से यह स्पष्ट नहीं है कि संदर्भित सभी संस्थान पंजीकृत थे या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से सरकार द्वारा संचालित संस्थान पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त होने चाहिए। इसलिए, यदि सुश्री अंजलि सिन्हा द्वारा अपने लेख में उल्लिखित प्रकृति की गतिविधियों को सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में किया जाता है, तो कोई केवल कल्पना कर सकता है कि गैर-पंजीकृत संस्थानों में क्या गलत हो सकता है, जो कानून से परे प्रबंधित हैं।

26. उनके पंजीकरण के अलावा, कानून में ऐसे संस्थानों द्वारा बाल देखभाल संस्थान की आवासीय क्षमता और उद्देश्य को दर्ज करने सहित कुछ हितकारी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 का नियम 21 (जिसे इसके बाद मॉडल नियम के रूप में संदर्भित किया गया है) बाल देखभाल संस्थानों के पंजीकरण के तरीके को निर्दिष्ट करता है और अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे संस्थानों के उप-कानूनों और संगठन के ज्ञापन, पदाधिकारी आदि की उपलब्धता प्रदान करता है। राज्य सरकार बच्चों की देखभाल और सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और आवास सुविधाओं, व्यावसायिक अध्ययन और पुनर्वास (अन्य बातों के अलावा) जैसे पहलुओं के आलोक में बाल देखभाल संस्थान के पंजीकरण के लिए एक आवेदन (प्रपत्र 27 में) पर विचार करने के लिए बाध्य है। तभी ही पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। राज्य

सरकार एक आवेदक संस्थान का निरीक्षण करने के लिए भी बाध्य है और हमें ऐसा लगता है कि यदि इस तरह का निरीक्षण ईमानदारी से किया जाता है, तो यह सुश्री अंजलि सिन्हा द्वारा संदर्भित संदिग्ध बाल देखभाल संस्थान के काले पेट(रहस्यमय एवं अपराधशील स्थल), यदि कोई हो, का खुलासा करेगा। जेजे अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने से ऐसे बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों के जीवन को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाने में मदद मिलेगी और तस्करी, यौन शोषण या यौन उत्पीड़न या यौन अपराधों और बच्चों का उत्पीड़न की संभावना भी कम होगी यदि बाल देखभाल संस्थानों का पंजीकरण पूरा नहीं हुआ है, तो उनके प्रबंधन की स्पष्ट रूप से निगरानी नहीं की जा सकती है। इसलिए, पहले चरण में एक गलत कदम से एक श्रृंखला प्रतिक्रिया हो सकती है और कुछ मामलों में शायद विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं जैसा कि सुश्री अंजलि सिन्हा द्वारा संस्थानों में बाल शोषण की घटनाओं से स्पष्ट है।

देखभाल के न्यूनतम मानक

27. सी. आर. सी. के अनुच्छेद 3 में आदेश दिया गया है कि सार्वजनिक या निजी समाज कल्याण संस्थानों, न्यायालयों, प्रशासनिक प्राधिकरणों या विधायी निकायों द्वारा किए गए बच्चों से संबंधित सभी कार्यों में प्राथमिक विचार के रूप में बच्चों का सर्वोत्तम हित होगा। सी. आर. सी. का अनुच्छेद 3 (3) विशेष रूप से राज्य दलों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थान सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करेंगे, विशेष रूप से सुरक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारियों और पर्यवेक्षण के क्षेत्रों में। हालांकि, संस्थानों के लिए निर्धारित देखभाल के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है यदि बाल देखभाल संस्थान चिन्हित और पंजीकृत नहीं हैं।

28. इस संबंध में आदर्श नियमों के अध्याय VI के प्रावधानों, विशेष रूप से नियम 26 से शुरू होने वाले नियमों की श्रृंखला की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। अन्य बातों के अलावा, ये नियम बाल देखभाल संस्थानों, भौतिक बुनियादी ढांचे, कपड़े, बिस्तर, प्रसाधन सामग्री और अन्य वस्तुओं,

स्वच्छता और स्वच्छता, दैनिक दिनचर्या, पोषण और आहार, चिकित्सा स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक और मनोरंजक सुविधाओं और पुनर्वास और ऐसे बच्चों का समाज में पुनः एकीकरण में वास्तविक प्रयासों से संबंधित हैं। बाल देखभाल संस्थानों के पंजीकरण के अभाव में इन सभी आवश्यकताओं को लागू नहीं किया जा सकता है।

29. एकीकृत बाल संरक्षण योजना, जो बाल देखभाल संस्थानों में देखभाल के न्यूनतम मानकों से भी संबंधित है, इनमें से कई आवश्यकताओं को पूरा करना और बच्चों के पुनर्वास कार्यक्रम और उनके मनोरंजन की ओर भी ध्यान आकर्षित करना, को संदर्भित करती है। बाल देखभाल संस्थानों के लिए निर्धारित देखभाल के न्यूनतम मानकों का अक्षर और भावना से पालन किया जाना चाहिए, न कि केवल कागज पर।

30. विद्वान न्यायमित्र ने हमें यह समझने के लिए कहा है कि दुर्भाग्य से, पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों में भी, कई वैधानिक सुविधाओं और आवश्यकताओं का अभाव है। यदि ऐसा है, तो हम केवल अपंजीकृत संस्थानों में बच्चों की जीवन स्थितियों की कल्पना कर सकते हैं।

31. किसी दिए गए मामले में, देखभाल के बुनियादी या न्यूनतम मानक को बनाए रखने में विफलता लापरवाही के रूप में कार्रवाई योग्य हो सकती है। **जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य**⁷ में इस न्यायालय ने *लापरवाही पर चार्ल्सवर्थ और पर्सी*⁸ के मामले का हवाला दिया और माना कि लापरवाही के आवश्यक घटक हैं: (1) देखभाल करने का कर्तव्य होना, जो प्रतिवादी द्वारा शिकायतकर्ता के प्रति किया जाता है; (2) कानून द्वारा निर्धारित देखभाल के उस मानक को प्राप्त करने में विफलता, जिससे ऐसे कर्तव्य का उल्लंघन होता है; और (3) क्षति, जो ऐसे उल्लंघन से कारणात्मक रूप से जुड़ी हुई है और कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, शिकायतकर्ता द्वारा सहन की गई है। इसलिए प्रभावी रूप से, यदि राज्य के अधिकारी यह सुनिश्चित नहीं करते हैं कि बाल देखभाल संस्थानों में देखभाल के न्यूनतम मानकों का पालन किया जाता है, तो वे लापरवाही के दोषी हो सकते हैं। चूंकि हमारा राज्य

कल्याणकारी राज्य है, इसलिए लापरवाह अधिकारियों के लिए लापरवाही के आरोप से खुद को मुक्त करना मुश्किल होगा और शायद बच्चों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप से भी।

अनुदान का उपयोग

32. सुनवाई के दौरान, हमने पाया कि कई मॉडल नियम हालांकि व्यवहार्य और फायदेमंद हैं, लेकिन केवल कागज पर ही मौजूद हैं और उनको एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत प्रावधानों या आवश्यकताओं को लागू करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। नियमों को लागू न करने के बहाने के रूप में सामने आने वाली चिंताओं में से एक धन की तथाकथित कमी थी। हम आश्चर्यचकित हैं कि इस तरह का बहाना आगे बढ़ाया गया था, भले ही बाल कल्याण के लिए आवंटित एक बड़ी राशि बिना खर्च किए पड़ी है।

33. इसलिए वास्तव में समस्या धन की कमी नहीं है, बल्कि उपलब्ध अनुदानों का सदुपयोग करने की इच्छाशक्ति का अभाव है। इस संदर्भ में विद्वान न्यायमित्र ने उदाहरण के तौर पर वर्ष 2013-14 के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत व्यय का विवरण हमारे ध्यान में लाया। इससे पता चलता है कि खर्च न किया गया अनुदान 3000 लाख रुपये से अधिक है। (इस आंकड़े में आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड राज्य द्वारा खर्च न की गई राशि शामिल नहीं है)। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि धन की कमी है। अभिलेख पर लाया गया चार्ट इस प्रकार है:-

अव्ययित अनुदानों का वर्षवार विवरण		
क्रमांक	राज्य का नाम	अव्ययित(राशि लाख में)
		2013-14
1	आंध्र प्रदेश	2999.28*
2	अरुणाचल प्रदेश	147.05

3	असम	148.47
4	बिहार	442.14
5	छत्तीसगढ़	0.00
6	गोवा	-
7	गुजरात	545.23
8	हरियाणा	238.92
9	हिमाचल प्रदेश	138.10
10	जम्मू एवं कश्मीर	-
11	झारखंड	147.21
12	कर्नाटक	57.94
13	केरल	291.52
14	मध्य प्रदेश	1084.67
15	महाराष्ट्र	0.00
16	मणिपुर	473.13
17	मेघालय	0.00
18	मिजोरम	0.00
19	नागालैंड	0.00
20	उड़ीसा	2.63
21	पंजाब	749.37
22	राजस्थान	253.33
23	सिक्किम	50.36
24	तमिलनाडु	589.22
25	त्रिपुरा	0.00
26	उत्तर प्रदेश	99.92
27	उत्तराखंड	333.92*
28	पश्चिम बंगाल	268.95
29	अंडमान और निकोबार द्वीप	-
30	चंडीगढ़	25.17

31	दादरा और नगर हवेली	9.63
32	दमन और दीव	58.63
33	दिल्ली	676.68
34	लक्षद्वीप	-
35	पुडुचेरी	-
कुल		6498.27

* राज्यों ने अपना व्यय विवरण (एसओई) प्रस्तुत नहीं किया है

हमें बताया गया है कि यही स्थिति अगले वर्षों में भी जारी रही।

34. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सुनिश्चित करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो, जिन्हें देखभाल और पोषण की आवश्यकता है। राज्य अनुदान के अक्षम उपयोग के साथ अपने दायित्वों को कम करने के लिए धन की अनुपलब्धता को नहीं जोड़ सकता है। हम दुखी हैं कि इस तरह का बहाना बनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय और राज्य आयोग

35. बेशक, संसद ने कई तरीकों से बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता की सराहना की है जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है और यही कारण है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया। वास्तव में उक्त अधिनियम की प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण है और न केवल आम तौर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति हमारे दायित्वों के एक हिस्से के रूप में भी है। बाल अधिकार अधिनियम, 2005 के संरक्षण आयोग डी की प्रस्तावना (जिसे इसके बाद 'सी. पी. सी. आर. अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) इस प्रकार है:

" राष्ट्रीय आयोग और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोगों और बच्चों के खिलाफ अपराध या बाल अधिकारों के उल्लंघन और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए बाल न्यायालयों के गठन का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम

भारत ने 1990 में संयुक्त राष्ट्र (यू. एन.) महासभा शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें बच्चों के उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास पर एक घोषणा को अपनाया गया था।

और क्योंकि भारत ने 11 दिसंबर, 1992 को बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (सी. आर. सी.) को भी स्वीकार कर लिया है

और क्योंकि सी. आर. सी. एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसके अनुसार है। हस्ताक्षरकर्ता राज्यों का दायित्व है कि वे कन्वेंशन में उल्लिखित बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं;

और क्योंकि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हाल ही में बच्चों के लिए जो पहल की है, उनमें से एक है बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर, 2003 को अपनाना;

और क्योंकि जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र मई 2002 में आयोजित बच्चों ने एक परिणाम दस्तावेज अपनाया जिसका शीर्षक था " बच्चों के लिए एक उपयुक्त विश्व "जिसमें वर्तमान दशक के सदस्य देशों द्वारा किए जाने वाले लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीतियाँ और गतिविधियाँ शामिल हैं;

और क्योंकि इस मामले में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए बच्चों से संबंधित सी. आर. सी. में निर्धारित मानकों और अन्य सभी प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय उपकरणों को ध्यान में रखते हुए; कानून बनाना समीचीन है

36. बच्चों के प्रति दायित्वों को पूरा करने के लिए, सी. पी. सी. आर. अधिनियम बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग (संक्षेप में 'एन. सी. पी. सी. आर. ') और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोगों (संक्षेप में 'एस. सी. पी. सी. आर. ') के गठन का प्रावधान करता है। इन आयोगों का उद्देश्य सी. पी. सी. आर. अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करना है और उनके

कार्यों की विशाल श्रृंखला को धारा 13 के साथ-साथ सी. पी. सी. आर. अधिनियम की धारा 24 में चित्रित किया गया है।

37. विद्वान न्यायमित्र ने बताया कि एन. सी. पी. सी. आर. और एस. सी. पी. सी. आर. बाल अधिकारों को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसे मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा भी इसकी अनदेखी की जाती है। उन्होंने बताया कि इनमें से कई निकायों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं और वास्तव में एनसीपीसीआर, एक समय में, एक वर्ष से अधिक समय तक के लिए किसी भी अध्यक्ष के बिना था। कुछ राज्य सरकारों ने भी एस. सी. पी. सी. आर. में रिक्तियों को भरने के लिए परवाह नहीं की है और कुछ अन्य लोगों ने कुछ पसंदीदा के लिए एस. सी. पी. सी. आर. का उपयोग किया है। यह फिर से, जैसा कि बताया गया है, और कुछ नहीं बल्कि एक संसदीय कानून के प्रावधानों को मौखिक सेवा प्रदान करना और बच्चों के संवैधानिक अधिकारों पर गंभीरता से ध्यान नहीं देना है। यह निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है।

38. इसी तरह, पॉक्सो अधिनियम के कार्यान्वयन में, एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सुश्री अंजलि सिन्हा द्वारा शिकायत किए गए यौन शोषण या यौन उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न के मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और पॉक्सो अधिनियम की धारा 44 एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर के कंधों पर एक बड़ा बोझ डालती है। ये पॉक्सो अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने का दायित्व अधिकारियों का है जैसा कि इसकी धारा 44 से स्पष्ट है जो निम्नानुसार है:

44. अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी-(1) धारा 3 के तहत गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, या जैसा भी मामला हो, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 17 के तहत बाल अधिकारों का संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग, उस अधिनियम के तहत उन्हें सौंपे गए कार्यों के अलावा, इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की भी निगरानी करेगा।

(2) राष्ट्रीय आयोग या, यथास्थिति, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट राज्यआयोग को, इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध से संबंधित किसी भी मामले की जांच करते समय, वही शक्तियां होंगी जो आयोगों के तहत उसमें निहित हैं। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 (2006 का 4)।

(3) राष्ट्रीय आयोग या, यथास्थिति, राज्य आयोग, जिसे उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है, इस धारा के तहत अपनी गतिविधियों को भी निम्नलिखित में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करेगा: बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 16.

39. हमारी राय में, यह आवश्यक है कि एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर को सीपीसीआर अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के संदर्भ में काम करने की अनुमति दी जाए और केवल बच्चों के लाभ के लिए। ये आयोग जहां भी आवश्यक हो, संवैधानिक न्यायालयों से संपर्क करने सहित जहां भी आवश्यक हो, कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। ये आयोग वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और यदि आवश्यक हो तो विशेष रिपोर्ट तैयार करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन यह बताया गया है कि इस आवश्यकता को शायद ही मुख्य रूप से लागू किया गया है क्योंकि इन आयोगों ने कानून के तहत काम करने में रुचि की कमी दिखाई है और आंशिक रूप से इन आयोगों में बड़ी संख्या में रिक्तियों के कारण भी इसे लागू नहीं किया जा सका है। ।

40. इसका मतलब यह नहीं है कि एन. सी. पी. सी. आर. या एस. सी. पी. सी. आर. अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत, एन. सी. पी. सी. आर. ने हाल ही में अपने वैधानिक दायित्वों को काफी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है और कुछ एस. सी. पी. सी. आर. भी हैं जो प्रासंगिक कानूनों के तहत अपने कार्यों को ईमानदारी से कर रहे हैं। दूसरी ओर, कुछ एस. सी. पी. सी. आर. हैं जो एकदम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। और वो या तो निष्क्रिय या बिना सिर के हैं। यह समझना मुश्किल है कि इन परिस्थितियों में, जेजे अधिनियम या पॉक्सो अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने की तो बात ही छोड़िए, को कैसे लागू किया जा सकता है।

41. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों की ओर से यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के प्रावधान ईमानदारी और निष्ठा से

कार्यान्वित हों और सी. पी. सी. आर. अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित वैधानिक आयोग को उक्त अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम के साथ-साथ जेजे अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र वैधानिक निकायों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

42. कानून के शासन में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार सहित सभी संबंधित लोगों द्वारा संसदीय कानून का पालन करना शामिल है और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि संबंधित सरकारें स्वेच्छा से और जानबूझकर संसद द्वारा गंभीरता से अधिनियमित कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं। हमें इस विषय पर और कुछ नहीं कहना है, सिवाय इसके कि संसद द्वारा गंभीरता से अधिनियमित कानूनों का इन आयोगों के प्रभावी कामकाज में बाधा डालकर अपमान नहीं किया जा सकता है, जैसे कि अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति ना करना

पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण

43. देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के भविष्य के संबंध में, जेजे अधिनियम में धारा 53 जैसे अनिवार्य प्रावधान हैं जो बाल देखभाल संस्थानों में पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण सेवाओं से संबंधित हैं। इस प्रावधान के तहत राज्य को ऐसे संस्थानों में बच्चों की बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जहां आवश्यक हो कानूनी सहायता और अधिक महत्वपूर्ण रूप से पहचान का प्रमाण प्राप्त करने में सहायता शामिल है। ऐसे उदाहरण हमारे संज्ञान में लाए गए हैं जहां बच्चे; विशेष रूप से परित्यक्त बच्चों के मामले में, जो अपने माता-पिता या स्थायी पते के बारे में कोई जानकारी देने में असमर्थ हैं आदि। ऐसे मामलों में, बच्चे के कल्याण के लिए पहचान का प्रमाण महत्वपूर्ण है, अन्यथा वह केवल एक आंकड़े तक सीमित हो जाता है।

44. पुनर्वास और पुनः एकीकरण सेवाओं के प्रावधान में कई पहलू हैं और इन्हें अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है, बल्कि इन्हें जेजे अधिनियम की धारा 54 के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए, जिसके तहत उक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों का निरीक्षण करना आवश्यक

है। निरीक्षण समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है, जो कम से कम तीन सदस्यों की टीम में, जिनमें कम से कम एक महिला और एक चिकित्सा अधिकारी होगा, आवंटित क्षेत्र में बच्चों को रखने वाली सभी सुविधाओं का कम से कम तीन महीने में एक बार दौरा करेगी। उनकी निरीक्षण रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके नियम 41 के तहत तैयार किए गए मॉडल नियमों का फॉर्म 46 काफी विस्तृत है और यदि फॉर्म को उचित गंभीरता से भरा जाता है, तो यह बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित होगा।

45. पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण का महत्व स्पष्ट रूप से सामने आता है यदि हम जेजे अधिनियम के उद्देश्य को समझते हैं जो कि पुनर्स्थापनात्मक न्याय को बढ़ावा देना है। जब तक पुनर्स्थापनात्मक न्याय के मूल तत्वों और सिद्धांतों को मान्यता नहीं दी जाती और उनका पालन नहीं किया जाता, तब तक कोई सार्थक पुनर्वास नहीं हो सकता, विशेष रूप से कानून के साथ संघर्ष में फंसे बच्चे का, जो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा भी है।

46. दुर्भाग्य से, पुनर्स्थापनात्मक न्याय शुरू करने में आने वाली समस्याओं में से एक यह है कि बाल देखभाल संस्थान में एक बच्चे को एक संख्या के रूप में माना जाता है और फॉर्म 7 के साथ पठित मॉडल नियमों के नियम 19 द्वारा अभिनिर्धारित किसी भी व्यक्तिगत बाल देखभाल योजना को शुरू करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। न्यायमित्र ने हमें सूचित किया कि प्रपत्र बहुत कम ही भरा जाता है (यदि बिल्कुल भी हो) और कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे सहित प्रत्येक बच्चे की जरूरतों पर बहुत कम या कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बाल देखभाल संस्थान में व्यक्तिगत बाल देखभाल योजनाओं को तैयार करने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए क्योंकि यह वास्तव में देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण का केंद्र है। बेशक, इस कवायद में कुछ विशेषज्ञता शामिल है, लेकिन जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था, हमारे देश में श्रमशक्ति की कोई कमी नहीं है और यह केवल राज्य सरकारों, केंद्र

शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की इच्छाशक्ति है जो जेजे अधिनियम, मॉडल नियमों के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन और विभिन्न प्रपत्रों को भरने और उनके विश्लेषण के रास्ते में आ रही है।

कार्मिकों का प्रशिक्षण

47. विद्वान न्यायमित्र द्वारा उठाए गए अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के संदर्भ में मॉडल नियमों के नियम 89 में पाया जाता है जो कि बच्चों से संबंधित मामलों में काम करने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण से संबंधित है। इस नियम में बाल न्यायालयों के कर्मचारियों, प्रधान मजिस्ट्रेटों और किशोर न्याय बोर्डों के सदस्यों, बाल कल्याण समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों, बाल देखभाल संस्थानों के प्रभारी व्यक्तियों सहित पुलिस अधिकारियों सहित जेजे अधिनियम के तहत विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों को न्यूनतम 15 दिनों के प्रशिक्षण का प्रावधान है। मॉडल नियमों के नियम 89 में यह भी कहा गया है कि राज्यों में न्यायिक अकादमी और पुलिस अकादमी के साथ-साथ राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण उचित प्रशिक्षण

मॉड्यूल, प्रशिक्षण नियमावली तैयार करे और कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करे। विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह बताया गया कि मैं इस नियम का जितना अधिक पालन नहीं किया जा रहा है उससे ज्यादा उलंघन किया जा रहा है और शायद ही कोई न्यायिक अकादमी या पुलिस अकादमी या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण जो 15 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह कहना कम से कम दुर्भाग्यपूर्ण है।

48. गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के महत्व को एक नकारात्मक उदाहरण देकर सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जो यह है कि जब तक संबंधित कर्मियों को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, यह काफी संभव है कि उचित मार्गदर्शन के अभाव में अजीब प्रथाएं और 'प्रक्रियाएं विकसित हो सकती हैं। यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि बच्चों को दत्तक ग्रहण के मामलों में संबंधित न्यायालयों द्वारा कुछ अत्यंत असामान्य और अव्यावहारिक आदेश पारित किए गए हैं। यह सही समय है कि उच्च न्यायालय अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें और हस्तक्षेप करें और उचित

सुधारात्मक कदम उठाएं। यह भी उचित समय है कि कार्मिकों के प्रशिक्षण को उचित महत्व दिया जाए। हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह हमारे ध्यान में लाया गया था कि अप्रशिक्षित या अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कर्मी अनजाने में यौन दुर्व्यवहार या यौन हमले या यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के जीवन के साथ खिलवाड़ सकते हैं।

विसंस्थागतिकरण ...

49. पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण के संदर्भ में, यह था

हमारे सामने प्रस्तुत किया गया कि बच्चों का संस्थागतकरण आवश्यक रूप से एकमात्र उपलब्ध विकल्प नहीं है। विद्वान न्यायमित्र के इस बात को सी. आर. सी. के अनुच्छेद 20 में भी समर्थन मिलता है। यह अनुच्छेद राज्य दलों को अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से पारिवारिक वातावरण से वंचित बच्चों को विशेष सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। यह अनुच्छेद पालक नियुक्ति, दत्तक ग्रहण में या यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त संस्थान में नियुक्ति के रूप में वैकल्पिक देखभाल का वर्णन करता है। यह स्पष्ट है कि अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला विकल्प देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे का संस्थागतकरण नहीं होना चाहिए और यह अंतिम उपाय है। कानून का उल्लंघन करने के आरोपी बच्चों से संबंधित सीआरसी के अनुच्छेद एफ 40 (4) में यह भी कहा गया है कि राज्य पक्ष "देखभाल, मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण, परामर्श, परिवीक्षा, पालक देखभाल, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण और संस्थागत देखभाल के अन्य विकल्प" सुनिश्चित करेंगे। वास्तव में, सी. आर. सी. की भावना को ध्यान में रखते हुए, जे. जे. अधिनियम स्वयं गोद लेने (अध्याय VIII), पालक देखभाल (धारा 44) और प्रायोजन जैसे संस्थागतकरण के विकल्पों को प्रोत्साहित करता है। (धारा 45)। इसे भी कुछ गंभीर विचार की आवश्यकता है, जैसा कि विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया है।

50. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हमारे ध्यान में लाया कि केंद्र सरकार ने दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के साथ-साथ पालन-पोषण देखभाल के लिए मॉडल दिशानिर्देश, 2016 तैयार किए हैं।

इन चीजों को न्यायालयों सहित सभी संबंधितों द्वारा लागू किया जाना, विशेष रूप से दत्तक ग्रहण करने वाले मुद्दों से निपटने वाले, की जरूरत है। हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जेजे अधिनियम, आदर्श नियम, विनियम और दिशानिर्देशों की समझ और सराहना में प्रशिक्षण अनिवार्य है और केवल इन दस्तावेजों की प्रतियां संबंधित कर्मियों को सौंपना आवश्यक है, भले ही वे न्यायिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी या सरकारी अधिकारी हों काफी नहीं है। किसी प्रकार का प्रशिक्षण नितांत आवश्यक है ताकि बच्चों के लाभ के लिए और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के लक्ष्य और उद्देश्यों को अक्षरशः लागू किया जा सके।

51. हमें इस स्तर पर इस बात पर जोर देना चाहिए कि बच्चों के कल्याण में रुचि रखने वाले सभी हितधारकों के लिए एक साथ एक साझा लक्ष्य की ओर काम करना बिल्कुल आवश्यक है।

।इस सामूहिक कार्य में न केवल सरकारी तंत्र बल्कि पुलिस, नागरिक समाज और न्यायपालिका भी शामिल होगी।

किशोर न्याय समिति

52. यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि न्यायपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में बहुत पीछे नहीं है किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के लागू होने के चार साल बाद भी, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सभी उच्च न्यायालयों से उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और उक्त अधिनियम के तहत गतिविधियों की निगरानी करने के लिए एक किशोर न्याय समिति का गठन करने का अनुरोध करने के लिए मजबूर किया। उच्च न्यायालयों का यह सुनिश्चित करने का संवैधानिक दायित्व है कि संविधान के तहत बच्चों सहित सभी नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित, सुरक्षित और सम्मानित किया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए, सभी उच्च न्यायालयों ने एक किशोर न्याय समिति का गठन किया है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और ये समितियां यह सुनिश्चित करती हैं कि अधिनियम के प्रावधानों को अक्षरशः लागू किया

जाए।बच्चों से संबंधित मुद्दों पर बेहतर समन्वय के लिए कुछ उच्च न्यायालयों ने किशोर न्याय समिति के लिए एक सचिवालय भी प्रदान किया है।

53. समय बीतने के साथ यह महसूस किया गया है कि उच्च न्यायालय में किशोर न्याय समिति के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है।यह हम सभी के लिए अब यह महसूस करने का समय है कि न्यायाधीशों को अब हाथीदांत के मीनार(वास्तविकता से अलग रहने) में रहने की आवश्यकता नहीं है।संवैधानिक न्यायालयों सहित सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों को गैर-न्यायिक कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करना होता है ताकि लोगों के मौलिक अधिकारों का सम्मान किया जा सके।यही वह वास्तविकता है जिसने जनहित याचिका के माध्यम से सामाजिक न्याय के मुद्दों में संवैधानिक न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। और यह वह है जिसके लिए न्यायालयों के न्यायाधीशों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1986, . के तहत गरीब लोगों और उन लोगों के लिए जो वित्तीय या अन्य बाधाओं के कारण कानूनी सेवाओं का खर्च नहीं उठा सकते हैं न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। इस संवैधानिक दायित्व और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में प्रत्येक किशोर न्याय समिति की चिंता और भागीदारी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।यह समान रूप से पुलिस सहित राज्य के संबंधित अधिकारियों का दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करे कि -प्रत्येक किशोर न्याय समिति के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें ताकि जेजे अधिनियम द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों और संवैधानिक दृष्टि को कम से कम समय में सफलतापूर्वक प्राप्त किया जाए।

सामाजिक अंकेक्षण

54. यह सुनिश्चित करने के उद्देश्यों के लिए कि जेजे अधिनियम का कार्यान्वयन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, यह आवश्यक है कि हर साल एक सामाजिक अंकेक्षण की जाए।सामाजिक अंकेक्षण आत्मनिरीक्षण के साथ-साथ सेवाओं में सुधार के कारण भी देती है।

55. सामाजिक अंकेक्षण ने जनताके प्रति जवाबदेही के लिए एक साधन के रूप में प्रासंगिकता प्राप्त की है। इसे "अपने हितधारकों के विचारों के आधार पर व्यवस्थित और नियमित निगरानी के माध्यम से एक विभाग के गैर-वित्तीय उद्देश्यों का मूल्यांकन"⁹ के रूप में परिभाषित किया गया है। एक सामाजिक अंकेक्षण को माना जाता है क्योंकि यह एक पारंपरिक सरकारी अंकेक्षण के पूरक के रूप में काम करता है, जो अक्सर 12 महीने के चक्रों में किया जाता है और हर बार एक अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करता है¹⁰। वास्तव में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा सामाजिक अंकेक्षण पर कार्य समूह की रिपोर्ट में यह राय दी गई थी कि भारतीय अंकेक्षण और लेखा विभाग द्वारा सामाजिक अंकेक्षण को सामाजिक क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के प्रदर्शन में एक आवश्यक प्रक्रिया और उपकरण के रूप में अंकेक्षण को मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए क्योंकि वे कार्यक्रम योजना, कार्यान्वयन और निगरानी¹¹ की सूक्ष्म स्तर की जांच को मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं।

56. सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता न केवल आत्मनिरीक्षण के लिए बल्कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए भी आवश्यक है। सामाजिक अंकेक्षण से बचने का कोई कारण नहीं हो सकता है, खासकर तब जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के साथ-साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया गया है। हमें यह आभास हो रहा है कि किसी अज्ञात कारण से केंद्र सरकार सामाजिक अंकेक्षण से कतरा रही है।

57. 17 अप्रैल, 2015 को सुनवाई में, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हमें सूचित किया कि 2007 में नियम अधिसूचित होने के बावजूद कोई सामाजिक लेखा परीक्षा नहीं की गई थी। भारतीय संघ को तब सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने के लिए एक नीति को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया था।³⁰ अक्टूबर, 2015 की सुनवाई में हमें सूचित किया गया कि सामाजिक अंकेक्षण के प्रारूपों को कमोबेश अंतिम रूप दे दिया गया है। नवंबर 2015 में किसी समय दायर किए गए अपने हलफनामे

9

10

11

में, यूनियन भारत सरकार ने बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, बाल गृहों, विशेष गोद लेने वाली एजेंसियों, खुले आश्रय/आश्रय गृहों, अवलोकन गृहों और विशेष गृहों के लिए आदर्श सामाजिक अंकेक्षण प्रारूपों की प्रतियां संलग्न की हैं। हलफनामे में कहा गया है कि इन प्रारूपों को प्रायोगिक परीक्षण के लिए 29 अक्टूबर, 2015 के पहले के हलफनामे में उल्लेखित चयनित राज्य परिचालित किया जाएगा।

58. हमें यह नहीं बताया गया कि क्या भारत संघ द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्रारूपों के संदर्भ में सामाजिक अंकेक्षण या प्रायोगिक परीक्षण के परिणाम, यदि कोई हो, करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन प्रारूपों का शीघ्रता से परीक्षण किया जाए ताकि कि जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन को और अधिक सार्थक बनाया जाए।

तकनीक और कंप्यूटर

59. हमें यह समझने के लिए कहा गया है कि देश में सभी बाल देखभाल संस्थानों का कोई डेटा बेस नहीं है। राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के सहयोग से उपलब्ध आंकड़ों को मान्य भी नहीं किया है या बाल देखभाल संस्थानों का मानचित्रण भी नहीं किया है। यह एक आवश्यक पहला कदम है क्योंकि यह कल्पना करना मुश्किल है कि बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों की देखभाल कैसे की जा सकती है यदि संस्थानों की संख्या, ऐसे संस्थानों में बच्चों की संख्या, बच्चों के बारे में प्रासंगिक जानकारी आदि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों और बाल देखभाल संस्थानों के अभिलेखों के संग्रह, संशोधन और पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी का अच्छा उपयोग किया जा सकता है।

60. केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सभी बाल देखभाल संस्थानों की पूरी सूची उनके पते और प्रभारी व्यक्ति या प्राचार्य अधिकारी के साथ-साथ इन बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों का पूरा विवरण के साथ बनाएँ। विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि ये सभी विवरण, हालांकि आवश्यक हैं, केंद्र सरकार या एनसीपीसीआर के पास उपलब्ध नहीं

हैं। इन सभी सूचनाओं की उपलब्धता केवल प्रौद्योगिकी के उपयोग और एक बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम से ही संभव है।

61. इसी तरह, किशोर न्याय के प्रभावी कामकाज के लिए बोर्डों के साथ-साथ बाल कल्याण समितियों के लिए यह आवश्यक है कि वे निर्बाध बिजली आपूर्ति इकाइयों के साथ कम्प्यूटर और प्रिंटर से लैस हों ताकि उनका दिन-प्रतिदिन का कामकाज सुचारु रूप से चल सके। खयाल रखा जाए। विद्वान न्यायमित्र ने बताया कि शायद यह बहुत अधिक की मांग हो सकती है क्योंकि उन्हें इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि बाल कल्याण समितियों या किशोर न्याय बोर्डों के पास पर्याप्त स्टेशनरी उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से एक उचित माँग की जानी चाहिए, जिसे आराम से संसाधित किया जाता है। हमारी राय में यदि इस निवेदन को स्वीकार किया जाता है तो यह एक बहुत ही खेदजनक स्थिति का संकेत देगा जिसमें किशोर न्याय बोर्डों और बाल कल्याण समितियों को कार्य करने के लिए बनाया गया है। इस सौतेले दृष्टिकोण को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि ये वैधानिक निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में बाल देखभाल संस्थानों पर आवश्यक पर्यवेक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

दिशा-निर्देश

62. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

1. जेजे अधिनियम की धारा 2(14) के तहत "देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे" की परिभाषा को एक संपूर्ण परिभाषा के रूप में व्याख्या नहीं किया जाना चाहिए। यह परिभाषा उदाहरणात्मक है और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए परिकल्पित लाभों को ऐसे सभी बच्चों तक बढ़ाया जाना चाहिए जिन्हें वास्तव में राज्य की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है।

2. केंद्र सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बाल देखभाल संस्थानों के पंजीकरण की प्रक्रिया 31 दिसंबर, 2017 तक पूरी हो जाए और संपूर्ण डेटा की पुष्टि और सत्यापन हो। सभी संबंधित अधिकारियों के पास जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। पंजीकरण प्रक्रिया में देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले सभी बच्चों का डेटाबेस भी शामिल होना चाहिए जिसे हर महीने अपडेट किया जाना चाहिए। डेटाबेस को बनाए रखते समय, संबंधित अधिकारियों द्वारा गोपनीयता और निजता के मुद्दों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
3. केंद्र सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे जेजे अधिनियम और मॉडल नियमों के अनुसार देखभाल के न्यूनतम मानकों को 31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले लागू करें।
4. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान (व्यय विवरण के साथ) के पूर्ण और उचित उपयोग के लिए योजनाएँ बनानी चाहिए। अनुदान को अव्ययित या आकस्मिक उपयोग के रूप में वापस करना किसी के लाभ को सुनिश्चित नहीं करेगा और प्रभावी रूप से बेकार खर्च है।
5. यह जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसे बच्चों के पुनर्वास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि सहित कई योजनाएँ हैं जिनका लाभ उठाया जाना चाहिए।

6. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे जेजे अधिनियम और मॉडल नियमों के अनुसार बाल देखभाल संस्थानों का नियमित निरीक्षण करने और ऐसे निरीक्षणों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए निरीक्षण समितियां गठित करें ताकि इन संस्थानों में बच्चों की जीवन स्थितियों में सकारात्मक बदलाव हो। इन निरीक्षण समितियों का गठन 31 जुलाई, 2017 को या उससे पहले किया जाना चाहिए और उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में बाल देखभाल संस्थानों का पहला निरीक्षण करना चाहिए और 31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

7. व्यक्तिगत बाल देखभाल योजनाओं की तैयारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बाल देखभाल संस्थान में प्रत्येक बच्चे के लिए एक बाल देखभाल योजना हो। हालांकि यह प्रक्रिया लंबी और बोझिल लग सकती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में इसकी आवश्यकता को कम करके नहीं आंका जा सकता। व्यक्तिगत बाल देखभाल योजना तैयार करने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है और इसे तुरंत शुरू किया जाना चाहिए और 31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले प्रत्येक बाल देखभाल संस्थानों में प्रत्येक बच्चे के लिए एक व्यक्तिगत बाल देखभाल योजना तैयार की जानी चाहिए।

8. जहाँ कहीं भी बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग की स्थापना नहीं की गई है या स्थापित होने के बावजूद अध्यक्ष या किसी एक या अधिक सदस्यों की अनुपस्थिति में पूरी तरह कार्यात्मक नहीं है, वहाँ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 31 दिसंबर, 2017 तक या उससे पहले

सभी रिक्तियों को समर्पित व्यक्तियों से भर दिया जाए। इस प्रकार गठित एससीपीसीआर को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए ताकि सभी को उनकी गतिविधियों के बारे में पता हो और वे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लाभ के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से योगदान दे सकें।

9. जेजे अधिनियम और मॉडल नियमों के अनुसार कर्मियों का प्रशिक्षण आवश्यक है। राज्यों में पुलिस अकादमियों और न्यायिक अकादमियों सहित पर्याप्त संख्या में अकादमियाँ हैं जो इस कार्य को कर सकती हैं। राष्ट्रीय स्तर के निकाय भी हैं जो प्रशिक्षण की इस प्रक्रिया में सहायता कर सकते हैं, जिनमें पुलिस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण ब्यूरो, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और स्थापित गैर सरकारी संगठन जैसे निकाय शामिल हैं। जहाँ भी संभव हो, प्रशिक्षण मॉड्यूल जल्द से जल्द तैयार किए जाने चाहिए।

10. अब समय आ गया है कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारें गैर-संस्थागतीकरण को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में देखें। यह आवश्यक नहीं है कि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को बाल देखभाल संस्थानों में रखा जाए। गोद लेने और पालन-पोषण जैसे विकल्पों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

11. सामाजिक लेखापरीक्षा के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। ऊपर उल्लिखित कुछ विधियों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा भी सामाजिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई है। ऐसी स्थिति में, यह आवश्यक है कि सामाजिक लेखापरीक्षा करने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ-साथ प्रत्येक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा

गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह संभवतः सबसे अच्छा संभव तरीका है जिसके द्वारा बाल देखभाल संस्थानों और जेजे अधिनियम और मॉडल नियमों के तहत अन्य निकायों के प्रबंधन और कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की निगरानी और पर्यवेक्षण किया जा सकता है।

12. जबकि प्रत्येक उच्च न्यायालय में किशोर न्याय समिति जेजे अधिनियम और आदर्श नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक समिति को सहायता के रूप में एक छोटे सचिवालय की आवश्यकता होगी। हम प्रत्येक किशोर न्याय समिति से अनुरोध करते हैं कि वह अपनी सहायता के लिए एक सचिवालय स्थापित करने पर गंभीरता से विचार करे और हम प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को प्रत्येक उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति को सहायता प्रदान करने और इस संबंध में किशोर न्याय समिति के साथ सहयोग करने का निर्देश देते हैं।

13. हम इस जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों में गहरी दिलचस्पी लेने और इस न्यायालय को हर समय प्रभावी सहायता प्रदान करने के लिए सुश्री अपर्णा भट्ट द्वारा किए गए योगदान को स्वीकार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति किशोर न्याय समिति को 1500 रुपये का मानदेय देगी। किशोर न्याय के मुद्दों के लिए उपलब्ध निधियों में से सुश्री अपर्णा भट्ट को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे।

14. हालांकि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित कुछ अन्य मुद्दे हो सकते हैं, हम इन मुद्दों को विचार के लिए खुला छोड़ते हैं और विद्वान न्यायमित्र को इस संबंध में उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हैं,

जिसमें ऊपर दिए गए निर्देशों में संशोधन या स्पष्टीकरण के लिए कोई आवेदन शामिल है।

15.भारत संघ को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश के संबंधित मंत्रालय या विभाग को हमारे निर्देशों को लागू करने के लिए सूचित करे और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सहायता से इन निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्र करे। इस संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट 15 जनवरी, 2018 को या उससे पहले इस न्यायालय में दायर की जानी चाहिए। रजिस्ट्री इस मामले को तुरंत सूचीबद्ध करेगी।

देविका गुजर्नल

निर्देश जारी किया गया।